RAJYA SABHA

Thursday, the 17th March, 1982/ 26th Phalguna 1904 (Saka)

The House met at eleven of the Clock. **Mr. Chairman** in the Chair.

TRIBUTE TO KARL MARX

MR. CHAIRMAN: On the fourteenth of this month, a hundred years ago, died Karl Marx, a social philosopher and a savant whose influence in this world has been no less than that of any religious leader, although he preached not religion but social reform. Advancing the philosophy of Hegel, and changing it from *idealism* to *materialism*, he adjusted the economic relations and forces in society and in conjunction with his life-long friend and co-philosopher Engels, he evolved theories which go under the name Marxism.

The world today cannot afford to ignore his philosophy and his followers and his opponents alike try to understand it to solve economic problems, especially the relationship of Capital and Labour, the ownership of private property and the role of the States and its Laws. One cannot face any of these problems without having regard to what Marx said, whether one aims at socialistic economy or communism.

In his death the world lost a man of outstanding intellect and an original thinker. Speaking for the honourable Members and myself, I honour the memory of this great man, a leader and a world reformer.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Paper Mill in Bihar

*261. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Asoka Paper Mill of Darbhanga in Bihar is working to its full capacity;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI S. M. KRISHNA): (a) to (c) During the year 1982 the Darbhanga Unit of Ashok Paper Mills could produce only 1438 tonnes of paper against an installed capacity of 13,500 tonnes per annum, due to power shortage and financial difficulties.

श्री शिव चन्द्र झा : सभापति महोदय, मेरे पास चिट्ठी है जो मैंने प्रधान मंत्री जी को लिखी है करीब करीब एक डेढ़ साल पहले, यदि चाहें तो मैं सारा पढ़ दूं।

श्री सभापति : पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने रेफरेंस दे दिया, आप घबराइये नहीं।

श्री सभापति : मुझे कभी घबराहट नहीं होती।

श्री शिव चन्द्र झा : करीब डेढ़ साल पहले उनको चिट्ठी मिल गई और उन्होंने कहा आई ऐम हैविंग दि मैटर लुक्ड इंटु। प्रधान मंत्री ने कहा कि कंसर्न्ड मिनिस्टर के पास मैंने भेज दी। फिर जवाब इनका आया कि असम और बिहार के अफसरों को बुलाकर देख रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सब मिलाकर एक डेढ़ साल तक लिखने के बाद भी परिस्थिति अच्छी नहीं है और वह कागज की मिल दरभंगा में जो है, जिसकी एक यूनिट असम में भी है, दम तोड़ रही है। बड़ी हैरानी की बात है कि पैसे की कमी या संचालन में

दुर्व्यवस्था की वजह से बिहार जैसे ही पिछड़ा हुआ है अंग्रेजी जमाने से और शायद यह सरकार की बड़ी नीति रखती है कि इसको पिछड़ा बनाये रखो। जो थोड़े बहुत उद्योग हुए हैं उनका भी संचालन ठीक ढग से नहीं हो रहा है। तो मैं मंत्री महोदय से पुछना चाहता हू कि क्या यह सही नहीं है कि उनको चलाने के लिए तुरन्त कुछ पैसे की, फंड की जरूरत है। मैंने इसके लिए पहले कई सुझाव दिये थे --

"Immediate provision for working capital to the extent of Rs. 5 crores by the holders of equity shares *i.e.*, the Governments of Bihar and Assam and the financial institutions like I.D.B.I./I.F.C.I. etc.

Even at the cost of repetition I will like to emphasise that nothing else can save this mill from immediate closure.

Reconstitution of the Board of Management with persons drawn from the profession. The Chairman or the Managing Director should be a man of excellence, wider acceptability and respectability. I will like to inform you that since last 8 months this company is running without a Managing Director.

Appointment of a team of experts to examine the various snags in the organisation..."

श्री सभापति : यह तो आपने सब अपनी राय जाहिर कर दी है। मगर सवाल आपका क्या है ?

श्री शिव चन्द्र झा : सवाल यह है कि इसका जो स्ट्रक्चर है अशोक पेपर मिल का वह ज्वायंट है असम के साथ। इसको ठीक से चलाने के लिये असम यूनिट के साथ इसको डिलिंक कर दिया जाए।

श्री सभापति : इसको डीलिंक करेंगे या नहीं यह आप जानना चाहते हैं ?

श्री शिव चन्द्र झा : डीलिंक इसलिये करवाना चाहता हूं कि दरभंगा मिल को असम के ऊपर डिपेंडेंट करना होता है। पल्प वहां पर बन सकता है और दूसरी सुविधाएं हैं, कोयला है; पावर शोर्टेज की बात भी इन्होंने कही है। यह हश-अप करने की बात है। हकीकत यह है कि उसकी बुनियादी जो रिक्वायरमेंट है फंड संचालन के लिये वह सरकार मुहैया नहीं कर रही है। मैनेजमेंट को ठीक नहीं कर रही है। कंपीटेंट आदमी वहां नहीं हैं इसलिये करीब करीब दो हजार मजदूर बेकार हैं। मेरा सवाल यह है कि इसको चलाने के लिये आप कितना पैसा दे रहे हैं ? जो संचालन की रिक्वायरमेंट है उसके लिये आपने कितना दिया है और मैनेजमेंट की कौन सी व्यवस्था है ?

SHRI S. M. KRISHNA: Sir, I appreciate the concern of the hon. Member about the non-functioning of the Asoka Paper Mills. There are three aspects which he has drawn our attention to: One is whether any delinking can be effected. Sir, this has a chequered history where the pulp has to come from the Assam unit and it has to be transported all the way to Darbhanga where there is another mill. We do not have pulping capacity in the Darbhanga unit of the Asoka Paper Mills. There are transportation difficulties. So, the question of delinking certainly is no panacea for the ills in which the Asoka Paper Mills is involved.

The second aspect of the question is whether there is financial constraint. Sir, here the Government of Bihar is involved, the Government of Assam is involved and then the financing institutions are involved. Now

finance is not as much of a constraint as it is with reference to personnel. In the Assam unit, the hon. Member would quite appreciate the fact, there are more than a hundred managers who have left the Assam unit, so much so that there is total dislocation of the functioning of the Assam unit also. Under the circumstances the Government of India have tried their very best to bring in some professionals in terms of bringing in the ITC who have a reputation for themselves. They have set up the Bhadrachalam Paper Plant. They have acquired about 24 per cent of the shares. So, it is now the ITC's problem to give a reorientation to the Asoka Paper Mills. Sir, the total accumulated loss in this Mill, according to us, is about Rs. 33 crores.

श्री शिव चन्द्र झा : दूसरा सवाल है कि इसमें असम सरकार और बिहार सरकार दोनों शामिल हैं लेकिन आप जानते हैं कि असम की सरकार इलिजिटिमेट सरकार है। यह आप जानते हैं कि चुनाव के बाद यह इलिजिटिमेट सरकार है उससे कोई लिजिटीमेट काम नहीं होगा। इसलिये मैं कहता हूं कि इसके मातहत नहीं चल सकती। इसी तरह से बिहार की सरकार है। वहां मिश्र की सरकार है-रोटन टु द कोर सरकार है, **(व्यवधान)** इसलिये मेरा यह कहना है कि केन्द्रीय सरकार, मैं नहीं कहता कि ये लोग भी दूध के धूले हुए हैं **(व्यवधान)** इनके मातहत आ जायेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जायेगा, लेकिन फिर भी कहता हूं कि यह अपने मातहत ले लें, सरकार इसको टेक ओवर कर ले। यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि हम लोग यहां पर हैं। हम लोग कब तक इस बात को कहते रहेंगे कि इस पेपर मिल को सरकार अपने हाथ में ले ?

श्री सभापति : आपसे क्या चलेगा ?

श्री शिव चन्द्र झा : हम लोग इनको लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि और अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट इसको अपने हाथ में ले ले तो ये हमारे नजदीक में रहेंगे हम पूछ सकेंगे। आई० डी० पी० आई० की खबर है कि आप इसको मल्टी नेशनल कम्पनीज को बेचने जा रहे हैं ... **(व्यवधान)** ।

श्री सभापति : आपका सवाल क्या है ?

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा सवाल यह है है कि आप इस पेपर मिल को अपने हाथ में ले रहे हैं या नहीं ? इसका आप नेशनेलाइजेशन कर रहे हैं या नहीं ?

श्री सभापति : तिवारी जी, आप इसको लेने के लिए तैयार हैं या नहीं, यह बता दीजिये ताकि इनकी बेचैनी दूर हो जाय।

SHRI S. M. KRISHNA: Sir, he has illegitimised the Assam Government and the Bihar Government and legitimised the Central Government and the Karnataka Government.

MR. CHAIRMAN: And himself.

SHRI S. M. KRISHNA: So that really does not take us far. About nationalisation, we will have to go into the financial implications involved. Right now we have so many units which have been nationalised and which we are finding extremely difficult to run. And the hon. Member is totally aware of the financial constraints and the resources which are involved in it.

श्री शिव चन्द्र झा : हाकी में हारने के लिये एशियाड पर ये लोग करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं, लेकिन अशोक पेपर मिल को चलाने के लिये इनके पास पैसा नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है।

श्रीमती मनोरमा पाण्डेय : श्रीमन, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि 18 अगस्त, 1982 को जो एक बैठक हुयी थी जिसमें उद्योग मंत्री जी, चेयरमैन, आई० डी० बी० आई० और बिहार सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्ज भी उपस्थित थे उसमें क्या फैसले लिये गये ?

SHRI S M. KRISHNA: Sir, to underscore the concern of the Central Government, the hon. Minister of Industry called a meeting on 18-8-1982 in which the representatives of the two State Governments and the financial institutions were also invited. It was decided at this meeting that the IDBI's proposal of the ITC associating with the management of Asoka Paper Mills was the best alternative for the revival of the company, and the financial institutions were asked to chip in, about Rs. 38.93 lakhs by the IDBI, Rs. 35 lakhs by the IFCI and Rs. 35 lakhs from the LIC. Sir, all these three financial institutions did give us money and it was only these Rs. 107 lakhs which came to our rescue to pay the workers their wages.

श्री रामानन्द यादव : सभापति जी, बिहार प्रदेश में, खास तौर से नार्थ बिहार में, कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं हैं। केवल 13 शुगर इंडस्ट्रीज हैं। इसके अलावा दूसरी टाइप की कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो वहां पर कागज बनाती है। पहले पहल इस इंडस्ट्री को चलाने के लिये श्री ठाकुर प्रसाद सिंह जी जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं, उनको वित्तीय संस्थाओं से काफी पैसा दिया गया। लेकिन श्री ठाकुर प्रसाद सिंह की एक दूसरी कंसर्न भी है।

श्री सभापति : उस वक्त तो बहुत अच्छी हालत थी। उसकी हालत अब खराब हुई है। उस पर कोई सवाल पूछिये।

श्री रामानन्द यादव : सभापति जी, आप बात सुन लें। करोड़ों रुपया वित्तीय संस्थाओं की तरफ से समस्तीपुर पेपर फैक्टरी को चलाने के लिये ठाकुर प्रसाद सिंह को दिया गया था ताकि उस मिल को चलाया जा सके, मजदूरों को पैसा दिया जा सके। लेकिन ठाकुर प्रसाद सिंह ने इस पैसे को अपनी शिपिंग कारपोरेशन में डायवर्ट कर दिया जो कि कानूनन गलत है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि करोड़ों रुपया जो इस मिल को चलाने के लिए दिया गया था उसको शिपिंग कारपोरेशन, बम्बई में क्या डायवर्ट कर दिया गया जिसके कारण इस मिल की स्थिति आज इतनी खराब हो गई है और चल नहीं पा रही है ? तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आज जो समस्तीपुर ठाकुर पेपर फैक्टरियां हैं, चाहे असम की यूनिट हो, यहां की यूनिट हो, जो भी उनके मालिक रहे हैं--वे ठाकुर पेपर मिल वित्तीय संस्थानों से पैसा लेकर दूसरी जगह अपने कन्सर्न में डाइवर्ट करते जा रहे हैं और इस प्रकार इस उद्योग की स्थिति खराब होती जा रही है। क्या सरकार इस बात की भी जांच करेगी कि इस मिल की स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई है ? क्या यह बात सही है कि वित्तीय अनुदानों को डाइवर्ट करके, समस्तीपुर पेपर मिल मालिकों ने इसकी स्थिति को खराब कर दिया है ? अगर यह बात सही है, तो सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

MR. CHAIRMAN: Has there been any diversion of funds?

SHRI S. M. KRISHNA: The mill was promoted in 1957 by the Maharaja of Darbhanga and in 1965 they abandoned it. In 1968 the revival proposition was taken up by the Governments of Bihar and Assam and

since then they were able to commission it and run-down of the way the mills have worked would give some information. In 1977,57 per cent of the installed capacity was utilised. In 1978, 62 per cent was utilised. In 1979, 46 per cent was utilised And in 1982 only 15 per cent was utilised. At this point of time it would be very difficult for us to come to an assessment whether any funds were really diverted at the inception. The honourable Member is trying to draw the attention of the House to what happened at that point of time. He has given some useful information and we will look into it.

SHRI RAMANAND YADAV: I have put a specific question—whether the proprietor, Mr. Thakur, diverted large amounts of money from Samastipur paper concern to his shipping corporation at Bombay of which also he was the proprietor.

SHRI S. M. KRISHNA: You would appreciate that the shipping corporation does not come under the Ministry of Industry. That is why I made a submission that he has given some information and we would look into it.

SHRI RAMANAND YADAV: Are you prepared to make an inquiry about the diversion of funds by the proprietor?

SHRIMATI PRATIBHA SINGH: His question was if money was given to the Paper Mills by the Government, whether that money was diverted and what happened...

MR. CHAIRMAN: I think the House would like to be informed after you have looked into this matter. That is all. I don't think it is necessary to linger over this any more.

Rise in cement prices

*262. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Cement Manufacturers' Association has recently approached Government for yet another rise in cement prices;

(b) if so, what is the extent of rise in prices asked for by them and approved by Government both in the case of Levy and non-Levy cement; and

(c) what are the reasons for such a demand for a rise in the price of cement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI VIRBHADRA SINGH): (a) to (c) Request have been received by the Government for allowing escalations in ex-works retention and F.O.R. price of Levy cement. Increase in ex-works prices amounting to Rs. 26.96 per tonne of levy cement so far sought by the industry is intended to compensate the producers for escalations in manufacturing costs upto June 1982. These requests are under examination of the Government. Non-levy cement being free from price and distribution control, its prices are not fixed by the Government.

SHRI DHULESHWAR MEENA: May I know from the honourable Minister the number and reasons for asking for increase in price and quantum both in levy and non-levy cement under the Govt. sector? Despite all these concessions to the cement industry, cement which is a scarce commodity, is not only being adulterated by the dealer but is also sold at a high premium. May I know what steps the Government propose to take for easy availability of cement, particularly non-levy cement, at a fixed price, and to prevent adulteration? I would also like to know the break-up of the figure of Rs. 26.96 per tonne upto June 1982 which the honourable Minister has indicated.

SHRI VIRBHADRA SINGH: In June 1982 the Cement Manufacturers Association—the CMA—requested the